राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, रविवार, 15 फरवरी 2026

वर्ष 14,अंक 296, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के स्टूडेंट चैप्टर का उद्घाटन किया गया..03

भागते चीनी जहाज को जापान ने दबोचा, भारी एक्शन हो गया!..04

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

सत्ता से बाहर होकर कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है! असम में गरजे PM मोदी, नॉर्थ-ईस्ट को बताया अष्ठलक्ष्मी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गुवाहाटी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस की तुलना 'जहर' से करते हुए कहा कि सत्ता से 10 साल दूर रहने के कारण यह पार्टी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है. उन्होंने जनता को आगाह किया कि कांग्रेस असम की शांति और संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है. वह शनिवार को गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा में बोल रहे थे. पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पार्टी असम को फिर से पुराने दौर में ले जाना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस असम को फिर से अशांति और अराजकता में झोंकना चाहती है।

पीएम मोदी ने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए असम को 'घुसपैठियों के हवाले' करना चाहती है. उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस का एजेंडा असम की असली पहचान और संस्कृति को मिटाना है. पीएम मोदी ने कांग्रेस की मानसिकता पर प्रहार करते हुए कहा, '10 वर्ष सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस और ज्यादा जहरीली हो गई है.' उनका इशारा था कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसके लिए राज्य की सुरक्षा से समझौता ही क्यों न करना पड़े।

'कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती'

कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो... जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती. आज की कांग्रेस हर उस विचार... हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है... जो देश का बुरा सोचता है. जो लोग देश के टुकड़े-टुकड़े करने का सपना देखते हैं... जो लोग, नॉर्थईस्ट को भारत से अलग करने के नारे लगाते हैं... वो कांग्रेस के लिए पूजनीय बन चुके हैं.।

बजट में रखा गया नॉर्थ-ईस्ट का ध्यान

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये मिलते थे. अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं. अगर पिछले 11 वर्ष की बात करें तो असम

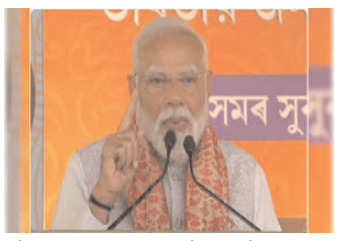

को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं. बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ-ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है. इस बार असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये मिलने वाले हैं. कांग्रेस के समय असम को कैसे पाई-पाई के लिए तरसा कर रखा जाता था. वो आपको भलीभांति याद होगा।

अगले 5 साल गेम-चेंजर: पीएम मोदी

विपक्ष पर हमले के बाद पीएम मोदी ने असम के विकास का रोडमैप भी रखा. उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल असम के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. इस दौरान कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं, जो असम की ग्रोथ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. पीएम ने जनता से अपील की कि विकास की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए यहां 'डबल इंजन' (केंद्र और राज्य में भाजपा) की सरकार फिर एक बार बहुत जरूरी है।

'नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्ठलक्ष्मी की तरह'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'अभी कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है. बजट के बाद असम का और नार्थईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है. जिस नार्थईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नार्थईस्ट की भक्तिभाव से सेवा कर रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्ठलक्ष्मी है. इस वर्ष का बजट... अष्टलक्ष्मी के लिए BJP-NDA के vision को और मजबूती देने वाला है।

भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ

भाजपा के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज भाजपा जहां पहुंची है, उसका श्रेय अगर किसी को मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाता है. हमारा विश्वास संगठन में है. हम राष्ट्रजीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं. इसलिए, इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के दर्शन करना बहुत बड़ा सौभाग्य है. हम लोग एक ही मंत्र को लेकर जिए हैं, हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं।

नरवणे विवाद का साइड इफेक्ट, बड़े अफसरों के किताब लिखने पर लग सकती है 20 साल की रोक, सरकार का प्लान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सेना और सरकार से जुड़े वरिष्ठ पदों पर रहे अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने को लेकर सख्त नियम लाने पर विचार किया जा रहा है. हिन्दुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार एक प्रस्ताव पर मंथन कर रही है, जिसके तहत सेना के वरिष्ठ अधिकारियों समेत बड़े सरकारी पदों पर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद कम से कम 20 साल का 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' तय किया जा सकता है. इस अवधि के पूरा होने से पहले वे अपनी किताब या संस्मरण प्रकाशित नहीं कर सकेंगे. अखबार के मुताबिक, इस संबंध में जल्द ही औपचारिक आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है. यह पूरा घटनाक्रम पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है. इस किताब में अगस्त 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सैन्य टकराव के दौरान की घटनाओं को लेकर किए गए दावों ने बीते दो हफ्तों से संसद में तीखी बहस छेड़ रखी है।

सरकार की क्या राय?

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह

मुद्दा चर्चा में आया. हालांकि यह बैठक के आधिकारिक 27 सूत्रीय एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन सामान्य चर्चा के दौरान कई मंत्रियों ने राय दी कि प्रभावशाली पदों पर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले एक लंबा कूलिंग-ऑफ पीरियड जरूरी होना चाहिए. सूत्रों ने बताया कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

नरवणे की किताब को लेकर क्यों विवाद?

नरवणे की किताबको लेकर विवाद 2 फरवरी को तब और बढ़ गया, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में इस आत्मकथा का हवाला देने की कोशिश की. सरकार ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है. इसके बाद राहुल गांधी इस किताब की एक कॉपी लेकर संसद पहुंचे, ताकि यह साबित किया जा सके कि किताब मौजूद है. जल्द ही इस किताब की पीडीएफ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी।

क्या कह रहा किताब का पब्लिशर?

इसके बाद प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि किताब का कोई भी हिस्सा, चाहे वह प्रिंट हो या डिजिटल, अवैध रूप से प्रसारित किया जा रहा है और यह कॉपीराइट का उल्लंघन है. प्रकाशक ने साफ किया कि वह ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा. इस बयान से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्जकर जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद मंगलवार को नरवणे ने भी चुप्पी तोड़ी और प्रकाशक के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी किताब न तो प्रकाशित हुई है और न ही किसी रूप में सार्वजनिक की गई है. बताया जाता है कि जनरल नरवणे की यह किताब जनवरी 2024 में प्रकाशित होनी थी. इससे पहले दिसंबर 2023 में समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसके कुछ अंश प्रकाशित भी किए थे. उसी दौरान नरवणे ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि उनकी किताब उपलब्ध है और इसके लिए एक ऑनलाइन प्री-ऑर्डर लिंक साझा किया था. अब इन्हीं तथ्यों को लेकर सरकार, विपक्ष और सुरक्षा तंत्र के बीच बहस और तेज हो गई है।

संक्षिप्त ख़बरें

राष्ट्रीय एकता महोत्सव पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ द्वारा लगायी गयी तीन दिवसीय प्रदर्शनी

राज्यसभा सांसद ने तीन दिवसीय प्रदर्शनी का फीता काटकर किया शुभारम्भ

प्रतापगढ़। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा घुइसरनाथधाम में 14 से 16 फरवरी तक तीन दिवसीय 31वें राष्ट्रीय एकता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, किसान कल्याण, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, डिजिटल सेवाओं एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी सरल

एवं चित्रात्मक माध्यम से प्रस्तुत की गई है। तीन दिवसीय प्रदर्शनी का राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने फीता काटकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी लालगंज शैलेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में पंजीकृत कलाकारों शिल्पी कठपुतली कला केन्द्र, योगी स्वर संगीत पार्टी, निराला लोकगीत एवं बिरहा पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। जनसामान्य एवं श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन कर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़ी 11 एफआईआर की जांच कर रही सीबीआई से दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 फरवरी) को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर एक पखवाड़े के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे. सीबीआई फिलहाल हिंसा से संबंधित 11 एफआईआर की जांच कर रही है. अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफारिशों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, 'सीबीआई वृंदा ग्रोवर की अर्जी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे. साथ ही, इन परिस्थितियों में पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए.' अदालत ने आगे कहा, 'हम आदेश देंगे कि यदि पहले के तनावपूर्ण माहौल के कारण लीगल एड कार्उसिल (एलएसी) उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो गुवाहाटी बार से एलएसी भेजे जा सकते हैं.' इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे. वरिष्ठ अधिवक्त वृंदा ग्रोवर एक पीड़ित की ओर से पेश हुईं।

पीड़ितों ने कहा है कि सीबीआई द्वारा जांचे जा रहे 27 मामलों में से कुछ में मुक़दमे की कार्यवाही बहुत धीमी चल रही है और पीड़ितों के परिवारों को मुक़दमे की

स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है. ऐसे ही एक मामले में मई 2023 की जातीय हिंसा के दौरान बलात्कार की शिकार हुई कुकी-जो समुदाय की एक युवती की पिछले महीने न्याय की प्रतीक्षा करते हुए मृत्यु हो गई. हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ़ हुए यौन अपराधों के दो मामलों में पीड़ितों की ओर से पेश हुई अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि परिवारों को अपने मामलों की प्रगति की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमने हाल ही में निचली अदालत के दस्तावेज देखे और पाया कि दोनों मामलों में आरोप-पत्र दाख़िल हो चुका है, लेकिन आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, सीबीआई उपस्थित नहीं है और मुख्य आरोपी अब तक पकड़े नहीं गए हैं.' पीड़ितों के एक अन्य समूह की ओर से पेश अधिवक्ता निज़ाम पाशा ने बताया कि 7 अगस्त 2023 के शीर्ष अदालत के आदेश के मद्देनज़र मौजूदा परिस्थितियों के कारण इन मामलों की निगरानी गौहाटी हाईकोर्ट में लंबित है. अदालत ने कहा, '2023 में हालात ऐसे थे कि निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की सुनिश्चितता के लिए इस अदालत को स्पष्ट निर्देश देना पड़ा था।'

वृंदा ग्रोवर ने यह भी कहा कि कुछ पीड़ित अब भी इंफाल जाकर हाईकोर्ट में पेश होने में सहज महसूस नहीं कर सकते. इस पर अदालत ने कहा, 'कानून के शासन को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को न्याय मिले, हम दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से कह सकते हैं कि गवाहों के बयान निर्भीक और स्वतंत्र वातावरण में कैसे दर्ज किए जाएं.' जस्टिस गीता मित्तल समिति अब तक राहत और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों पर अदालत को 42 रिपोर्टें सौंप चुकी है. इस पैनल में जस्टिस गीता मित्तल (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय), जस्टिस शालिनी पी जोशी, और जस्टिस आशा मेनन शामिल हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मणिपुर में मौजूदा स्थिति शांतिपूर्ण है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुधार हुआ है. अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 26 फ़रवरी को करेगी. हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा आयोजित एक रैली के बाद हुई थी. इसके बाद राज्य भर में झड़पें फैल गईं और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी. इस संघर्ष में अब तक 270 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।

'बदनामपुर' बन गया कानपुर, योगी सरकार पर बरसे अखिलेश, कहा- हादसों और झगड़ों का बन गया शहर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्तारुढ़ पार्टी ने कानपुर को बर्बाद कर दिया है और कभी फलते-फूलते इंडस्ट्रियल हब को अब 'बदनामपुर' बना दिया है. कानपुर स्थित सिविल लाइंस में अखिलेश यादव ने कल शुक्रवार को कहा कि यह शहर अब कार पलटने, पुलिस-वकील के झगड़े और स्क्रिप्टेड एनकाउंटर के लिए हेडलाइन बन रहा है. उन्होंने कहा कि कानपुर, जो कभी अपनी टेक्सटाइल मिलों और मैन्युफैक्चरिंग बेस के लिए जाना जाता था, वो अब सड़क हादसों, झगड़ों और प्रशासनिक नाकामियों से जुड़ा हुआ है, उन्होंने दावा किया कि गवर्नेंस में 'ब्रेकडाउन' दिखाता है।

कानपुर में बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का वादा

ऐतिहासिक लाल इमली टेक्सटाइल मिल

के बंद होने और गंगा में बिना ट्रीट किए सीवेज बहने के मुद्दे का जिक्र करते हुए, अखिलेश ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अक्षमता के जरिए शहर की विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाया. प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सत्ता में फिर से लौटने पर बदलाव का वादा करते हुए, पूर्व सीएम ने कहा कि उनकी सरकार यहां पर 'लखनऊ से भी बेहतर' रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट बनाएगी, लाल इमली मिल को फिर से चालू करेगी और बड़े इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनाएगी. उन्होंने पनकी पावर प्लांट में बार-बार बिजली जाने और देरी को भी लोकल इंडस्ट्री और रोजगार के लिए बड़ा बाधक बताया।

'जाम सिटी' भी बन गया कानपुर

केंद्र की स्मार्ट सिटी पहल पर निशाना साधते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर अब ट्रैफिक जाम की वजह से 'जाम सिटी' बन गया है. दिन में पहले गंगा बैराज हिस्से से शेयर किए गए एक वीडियो का जिक्र करते हुए, उन्होंने दावा किया कि यहां पर लोग करीब 90 मिनट तक फंसे रहे, और लखनऊ तथा कानपुर के बीच 45 मिनट के ट्रैवल टाइम के दावे पर भी सवाल उठाया. संसद में विपक्षी सांसदों को नहीं बोलने देने की बात करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि संसद में विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है. साथ उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी मजाक उड़ाया और कहा कि एक सच्चा योगी गुस्से या पावर से नहीं चलता. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रशासनिक नाकामियों और कैबिनेट विस्तार जैसी देरी से ध्यान हटाने के लिए एनकाउंटर और लॉ-एंड-ऑर्डर की कार्रवाइयों का इस्तेमाल कर रही है. वाराणसी में दाल मंडी का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उन इलाकों में चुन-चुनकर तोड़-फोड़ की जा रही है जहां BJP को वोट नहीं मिलते।

कांग्रेस ने टीपू सुल्तान को बताया शौर्य का प्रतीक, CM फडणवीस बोले- छत्रपति शिवाजी से तुलना करना शर्मनाक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी और टीपू सुल्तान को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने छत्रपति शिवाजी से टीपू सुल्तान की तुलना की है. इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को शर्मनाक बताया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने जिस प्रकार से छत्रपति महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम उसकी निंदा करते हैं. उनको अपने इस बयान पर शर्म आनी चाहिए. छत्रपति महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया. और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाले टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी से करने की बात अगर कांग्रेस करती है तो ये शर्मनाक है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोटों के लालच में ये जितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसे सहन नहीं करेगा और हम भी इसे सहन नहीं करेंगे।

क्या बोले थे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष?

महाराष्ट्र के बुलढाना में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य जिस तरह का है और 'स्वराज्य' नाम का उन्होंने जो एक विचार दिया है. ठीक उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए, उनके काफी समय बाद, उनका आदर्श लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था. उस अर्थ में, टीपू सुल्तान एक शौर्य दिखाने वाले योद्धा होकर गए. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वे भारत के एक भूमिपुत्र (सपूत) होकर गए. उन्होंने कभी भी किसी भी जहरीली या विकृत विचारधारा को अपने करीब नहीं आने दिया. इसलिए शौर्य के प्रतीक के रूप में हम टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के समकक्ष (समान) मानते हैं।

मालेगांव में भी टीपू को लेकर बवाल

वहीं, महाराष्ट्र में मालेगांव में भी टीपू सुल्तान को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं. दरअसल मालेगांव की डिप्टी मेयर और समाजवादी पार्टी नेता शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने अपने आधिकारिक चैंबर में उस जगह पर टीपू सुल्तान की तस्वीर टांगी है, जहां आम तौर पर महात्मा गांधी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाने की परंपरा रही है. लेकिन, उनके इस फैसले से बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. बीजेपी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस, AIMIM और इस्लाम पार्टी पर हमला बोला है. उनका कहना है कि इनके आदर्श बाबर, गजनी, मुगल,औरंगजेब और टीपू सुल्तान हैं।

बांग्लादेश में नयी सरकार बनने के बाद भारत के साथ संबंध बेहतर होने की उम्मीदः उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में नयी सरकार बनने के बाद भारत के उसके साथ संबंध बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में स्थिरता से भारत को लाभ होगा। श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक एग्रीटेक महोत्सव 'गोंगुल' के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा, 'हमारे पड़ोसी देश जितने अधिक स्थिर होंगे, उतना ही हमें फायदा होगा। कोई भी देश युद्ध या अपने किसी पड़ोसी देश को अस्थिर नहीं देखना चाहता फिर चाहे वह बांग्लादेश हो, श्रीलंका, नेपाल या कोई अन्य देश हो।' उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहे और वह स्थिर तथा समृद्ध बने। अब्दुल्ला ने कहा 'हमें उम्मीद है कि वहां सरकार गठन के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे, जिनमें कुछ कड़वाहट आ गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से किसानों तक प्रौद्योगिकी आधारित जैविक समाधान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा, 'लाखों लोग इस महोत्सव में आ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। यदि व्यापार समझौते के बाद हमें अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी है और उनका कृषि उत्पाद हमारे बाजार में आएगा, तो हमें अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ानी होगी। इस दिशा में यह महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'BJP को आज प्रिविलेज कमेटी याद आ रही', दिल्ली विस के एक्शन पर भड़के AAP नेता सौरभ भारद्वाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी वीडियो मामले में दिल्ली विधानसभा ने पंजाब के तीन अफसरों को नोटिस भेजकर 20 फरवरी तक जवाब मांगा है. पूरे मामले को लेकर लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भड़क गए हैं. सौरभ ने कहा कि भाजपा को आज प्रिविलेज कमेटी याद आ रही है. ऐसा करने से पहले केंद्र और एलजी को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए।

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दस साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही. प्रिविलेज के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने कभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को विधानसभा समिति के सामने पेश नहीं होने दिया. आप विधायक सवाल लगाते थे, दिल्ली पुलिस से कि हमारे यहां नशा बिक रहा है, हमारे यहां मर्डर हो रहे हैं और हमारे यहां गलत काम हो रहे हैं. इन सभी सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस से नहीं आता था. ये कहा जाता था कि इस लेजेस्टिव असेंबली की पावर नहीं है कि वो दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे. वही भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि पंजाब का डीजीपी हमे यहां आकर रिपोर्ट करे। ये तो

बहुत गजब बात हो गई।

BJP ने संस्थाओं को किया तहस-नहस

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए बीजेपी ने इन संस्थाओं को तहस-नहस कर दिया है. अब बीजेपी चाह रही है कि इन्ही संस्थाओं के जरिए वो पंजाब के डीजीपी को तलब कर ले, लेकिन इससे पहले दिल्ली बीजेपी सरकार, केंद्र और एलजी को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए. बताया जा रहा है कि पंजाब की आप सरकार आतिशी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रदेश की सरकार भारी पड़ेगी।

20 फरवरी तक मांगा जवाब

दरअसल, आतिशी वीडियो मामले में दिल्ली विधानसभा में जालंधर पुलिस कमिश्नर को फिर नोटिस भेजकर 20 फरवरी तक जवाब मांगा है. दिल्ली विस सचिवालय की ओर से पंजाब के अतिरिक्त सचिव (गृह), पंजाब डीजीपी गौरव यादव और जालंधर के पुलिस कमिश्नर को पत्र जारी कर निर्धारित समय तक जवाब न देने पर फटकार लगाई है. इससे पहले 12 फरवरी तक स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन जवाब न मिलने पर अब 20 फरवरी तक अंतिम अवसर दिया गया है।

जवाब न मिलने पर होगा एक्शन

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि तय समय में जवाब न आने पर विशेषाधिकार हनन और अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है. यह कार्रवाई दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी से जुड़ा है. उन पर सदन की कार्यवाही के दौरान सिख गुरुओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था. इसी संदर्भ में शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

बांग्लादेश में सत्ता का पुनर्संयोजन: भारत के लिए अवसर-संकेत

[बांग्लादेश की नवधारा और भारत की नीतिगत परीक्षा]

[बांग्लादेश में बदलाव की गूंज: जनता से जन्मा नया युग]

बांग्लादेश में हालिया चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की स्पष्ट और सशक्त अभिव्यक्ति बनकर सामने आया है। 12 फ़रवरी 2026 को हुए इस ऐतिहासिक मतदान में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 299 क्षेत्रों वाले चुनाव में 209-212 सीटें जीतकर निर्णायक बहुमत हासिल किया। यह परिणाम वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक असंतोष, प्रशासनिक कमज़ोरियों और लोकतांत्रिक अपेक्षाओं का स्वाभाविक नतीजा है। इस जनादेश ने बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा दी है और क्षेत्रीय संतुलन पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारत के लिए यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पड़ोसी देश की स्थिरता, नीतियाँ और नेतृत्व सीधे उसकी सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक हितों से जुड़े हुए हैं। यह चुनाव केवल सरकार बदलने की घटना नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की आधारशिला रखने वाला महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है। इस परिवर्तन की धुरी में तारीक रहमान का नेतृत्व सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाता दिखाई देता है। सत्रह वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद उनकी स्वदेश वापसी और फिर दो सीटों से निर्णायक जीत, बांग्लादेशी राजनीति में दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। उन्होंने स्वयं को केवल एक राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और प्रतिरोध से तपकर निकले नेता के रूप में स्थापित किया है। उनका चुनावी अभियान सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने जनता के मन में यह विश्वास जगाया कि व्यवस्था को बदला जा सकता है और शासन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। भारत के लिए यह तथ्य विशेष महत्त्व रखता है कि उन्होंने सार्वजनिक मंचों से क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार विस्तार और स्थिर संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि यह दृष्टिकोण ठोस नीतियों में बदलता है, तो भारत-बांग्लादेश संबंधों को नई ऊर्जा और मजबूती मिल सकती है।

इस राजनीतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि वर्ष 2024 के छात्र आंदोलनों में गहराई से जुड़ी हुई है, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को जड़ से हिला दिया था। उनका सत्ता से हटना केवल एक सरकार का अंत नहीं, बल्कि केंद्रीकृत शासन, कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन के विरुद्ध जनता के व्यापक असंतोष की खुली अभिव्यक्ति था। इसके बाद गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व मुहम्मद यूनुस ने किया, जिन्होंने सीमित समय और दबावपूर्ण परिस्थितियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया। इस संक्रमणकाल में भारत ने संयम, संतुलन और संवाद की नीति अपनाई, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता को फैलने से रोका जा सका। यह भारत की परिपक्व और जिम्मेदार कूटनीति का स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। बीएनपी की इस ऐतिहासिक विजय का सबसे मजबूत आधार जनता का गहरा और व्यापक असंतोष रहा है। बेरोज़गारी, बढ़ती महंगाई, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक दमन ने आम नागरिक के धैर्य की सीमा को तोड़ दिया था। बीएनपी ने 'लोकतंत्र की बहाली' और 'नया बांग्लादेश' जैसे प्रभावशाली नारों के माध्यम से इस असंतोष को संगठित राजनीतिक चेतना में परिवर्तित किया। इसके विपरीत, जमात-ए-इस्लामी गठबंधन अपेक्षित जनसमर्थन हासिल करने में असफल रहा। भारत के दृष्टिकोण से यह स्थिति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि कट्टरपंथी शक्तियों को सीमित समर्थन मिलना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे सीमा पार उग्रवाद और अस्थिरता की आशंकाएं फिलहाल कम होती हुई दिखाई देती हैं।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते केवल औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास, संस्कृति और आर्थिक सहयोग की गहरी नींव पर टिके हुए हैं। लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी साझा सीमा, व्यापारिक मार्गों का विस्तृत जाल और पीढ़ियों से जुड़े सामाजिक संबंध दोनों देशों को स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनाते हैं। भारत के लिए बांग्लादेश पूर्वोत्तर राज्यों की जीवनरेखा, समुद्री संपर्क का प्रमुख द्वार और क्षेत्रीय व्यापार का अहम सेतु है। अतीत में खालिदा जिया के कार्यकाल में द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिली थी। अब नई सरकार से भी अपेक्षा है कि वह ऊर्जा, रेल, बंदरगाह और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाकर आर्थिक साझेदारी को और सशक्त बनाएगी। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी स्थायित्व मिलेगा। सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग भारत-बांग्लादेश संबंधों की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कड़ी है। अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव व्यापार और आतंकी नेटवर्क जैसी चुनौतियाँ दोनों देशों के लिए समान रूप से चिंता का विषय हैं। शेख हसीना सरकार के दौरान इन मुद्दों पर कड़ा नियंत्रण देखने को मिला था, जिससे सीमा क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थिरता बनी रही। अब बीएनपी सरकार से भी उसी स्तर की प्रतिबद्धता और सतर्कता की उम्मीद की जा रही है। यदि नई सरकार इस मोर्चे पर दृढ़ और निरंतर प्रयास करती है, तो भारत-बांग्लादेश सुरक्षा सहयोग और अधिक मजबूत होगा। इसके साथ ही, आर्थिक सुधार, विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकालिक लाभ पहुँचा सकती है, जहाँ स्थिरता और विकास एक-दूसरे के पूरक बनकर उभरेंगे। इस चुनाव की सबसे सकारात्मक और आश्वस्त करने वाली विशेषता कुल मिलाकर शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण रही, हालांकि छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी हुईं। विपक्ष, अंतरिम सरकार और प्रशासन ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए जिम्मेदार व्यवहार का परिचय दिया। यह संकेत देता है कि बांग्लादेश धीरे-धीरे राजनीतिक परिपक्वता और संस्थागत मजबूती की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, असली परीक्षा अब शुरू होती है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण, न्यायिक स्वतंत्रता, मीडिया की स्वायत्तता और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर ठोस और निरंतर कार्रवाई आवश्यक होगी। भारत के लिए भी यह समय है कि वह केवल सरकारों तक सीमित न रहे, बल्कि संस्थागत और सामाजिक स्तर पर भी रिश्तों को मजबूत करे, ताकि द्विपक्षीय संबंध स्थायी, भरोसेमंद और भविष्य की चुनौतियों के प्रति सक्षम बन सकें। आज बांग्लादेश जिस नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है, वह केवल वर्तमान की दिशा नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के भविष्य को भी आकार देगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की यह ऐतिहासिक विजय देश के लिए नई उम्मीदों, नई जिम्मेदारियों और नई अपेक्षाओं का संकेत है, जबकि भारत के लिए यह सहयोग और साझेदारी को नई ऊंचाई देने का अवसर बनकर उभरी है। अब समय आ गया है कि दोनों देश पुराने अविश्वास, राजनीतिक संदेह और बीती हुई कटुताओं को पीछे छोड़कर साझा हितों पर आधारित मजबूत संबंध विकसित करें। यदि नई सरकार पारदर्शिता, स्थिरता और विकास को प्राथमिकता देती है और भारत संतुलित व दूरदर्शी नीति अपनाता है, तो यह साझेदारी पूरे दक्षिण एशिया के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की मिसाल बन सकती है। यही वह क्षण है, जब दूरदृष्टि और जिम्मेदारी मिलकर भविष्य की मजबूत आधारशिला रख सकती हैं।

प्रो. आरके जैन

वैलेंटाइन: प्रदर्शन बनाम आत्मिक संवेदना

वर्तमान समय में वैलेंटाइन दिवस भारतीय समाज में केवल एक तिथि नहीं, बल्कि विमर्श और विवाद का एक द्वंद्व बन चुका है। प्रतिवर्ष फरवरी के इस पखवाड़े में प्रेम की चर्चा जितनी तीव्र होती है, उसका विरोध भी उतना ही मुखर होता है। किंतु इस शोर के बीच हम अक्सर उस मूल प्रश्न को भूल जाते हैं कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या यह केवल सार्वजनिक प्रदर्शन और उपहारों के आदान-प्रदान तक सीमित है, अथवा यह एक गहरी आत्मिक संवेदना है जिसे आज के बाजारवाद ने जकड़ लिया है? भाषाई दृष्टि से देखें तो 'वैलेंटाइन' शब्द लैटिन के 'वेलनटिनस' से उपजा है, जिसका अर्थ है-शक्तिशाली, साहसी और दृढ़ हृदय वाला। यह परिभाषा प्रेम के उस प्रचलित स्वरूप को चुनौती देती है जिसे हम आज केवल कोमल भावनाओं या क्षणिक आकर्षण के रूप में देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से संत वैलेंटाइन ने दमनकारी सत्ता के विरुद्ध खड़े होकर मानवीय संबंधों की गरिमा की रक्षा की थी। अतः वैलेंटाइन का मूल भाव दुर्बल भावुकता नहीं, बल्कि वह आत्मिक शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस प्रदान करती है।

आज वैलेंटाइन का अर्थ बदलकर गुलाब, महँगे उपहार और सोशल मीडिया तथा सार्वजनिक स्थानों पर किए जाने वाले प्रदर्शन तक सिमट गया है। बाजार ने इस मानवीय संवेदना को एक 'उत्पाद' में बदल दिया है। जब प्रेम का पैमाना 'उपभोग' बन जाता है, तब उसकी पवित्रता का क्षरण निश्चित है। आज की युवा पीढ़ी जिसे प्रेम समझ रही है, वह अक्सर केवल बाह्य आकर्षण और सार्वजनिक प्रदर्शन की होड़ है। यही वह बिंदु है जहाँ सांस्कृतिक विरोध के स्वर जन्म लेते हैं। विरोध प्रेम का नहीं, बल्कि उसके उस विकृत और बाजारी स्वरूप का है जो मर्यादाओं की सीमा लांघता प्रतीत होता है। भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में प्रेम कोई नई या आयातित अवधारणा नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम को 'काम' से ऊपर उठाकर 'राम' तक ले जाने की परंपरा रही है। जहाँ पश्चिमी बाजारवाद प्रेम को 'अधिकार' की तरह देखता है, वहीं भारतीय मनीषा इसे 'कर्तव्य' और 'त्याग' के रूप में परिभाषित करती है। राम-सीता का संबंध केवल दांपत्य नहीं, बल्कि लोक-मर्यादा की स्थापना है। कृष्ण का प्रेम वात्सल्य, सखा-भाव और अटूट श्रद्धा का विस्तार है। बुद्ध की करुणा और कबीर की प्रेम-साधना यह बताती है कि प्रेम जब परिपक्व होता है, तो वह केवल दो व्यक्तियों तक सीमित न रहकर संपूर्ण सृष्टि के लिए 'संवेदना' बन जाता है। समस्या वैलेंटाइन दिवस मनाने में नहीं, बल्कि उसे मनाने के 'तरीके' और 'दृष्टिकोण' में है। यदि हमारे संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान, संवाद में शालीनता और व्यवहार में मर्यादा है, तो वह प्रेम वंदनीय है। किंतु यदि यह केवल एक दिन का दिखावा, प्रदर्शन है और शेष वर्ष उपेक्षा है, तो यह प्रेम के मूल विचार के साथ छल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम 'प्रदर्शन' की चकाचौंध से बाहर निकलकर 'संवेदना' के धरातल पर लौटें। प्रेम को 'वस्तु' मानने के बजाय उसे 'मूल्य' के रूप में स्वीकार करें।

वैलेंटाइन दिवस को न तो अंध-विरोध की कसौटी पर कसना चाहिए और न ही इसके वैश्विक बाजारीकरण में बह जाना चाहिए। यह आत्ममंथन का अवसर है कि क्या हम अपने संबंधों में उस 'वेलनटिनस' अर्थात् साहस और दृढ़ता को समाहित कर पा रहे हैं? जिस दिन हमारे आचरण में मर्यादा और हृदय में निस्वार्थ करुणा का वास होगा, उस दिन कैलेंडर की हर तारीख 'प्रेम पर्व' बन जाएगी। प्रेम जब प्रदर्शन की बेड़ियाँ तोड़कर आत्मिक संवेदना का मार्ग अपनाता है, तभी वह शाश्वत होता है।

डा मनमोहन प्रकाश

नई सत्ता, नए संकेत भारत बांग्लादेश रिश्तों और हिंदू सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा?

बांग्लादेश की राजनीति में लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्पष्ट जीत और उसके नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना ने न केवल ढाका की सत्ता संरचना को बदला है, बल्कि नई दिल्ली की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को भी सक्रिय कर दिया है। चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट किया है कि मतदाताओं ने स्थिरता, अनुभव और राजनीतिक विरासत को प्राथमिकता दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस परिवर्तन का भारत-बांग्लादेश संबंधों और विशेष रूप से बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक रूप से गहरे जुड़े रहे हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर हाल के वर्षों तक दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार, जल बंटवारे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग किया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध अपेक्षाकृत प्रगाढ़ रहे। सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी सहयोग और पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रांजिट सुविधाओं ने द्विपक्षीय भरोसे को मजबूत किया। ऐसे में सत्ता परिवर्तन को स्वाभाविक रूप से एक नए संतुलन की तलाश के रूप में देखा जा रहा है।

तारिक रहमान की वापसी और उनकी पार्टी की बहुमत के साथ जीत ने यह संकेत दिया है कि बांग्लादेशी मतदाता एक मजबूत राजनीतिक केंद्र चाहते हैं। हालांकि बीएनपी का अतीत भारत के साथ संबंधों को लेकर मिश्रित रहा है, लेकिन वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियाँ किसी भी नई सरकार को व्यावहारिक कूटनीति अपनाने के लिए बाध्य करती हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था निर्यात, विशेषकर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, और क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर है। भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार और रणनीतिक साझेदार है। इसलिए टकराव की राजनीति के बजाय सहयोग की राह चुनना नई सरकार के हित में होगा।

जहाँ तक हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न है, यह विषय केवल आंतरिक राजनीति का मुद्दा नहीं, बल्कि द्विपक्षीय संवेदनशीलता का भी हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। समय-समय पर सांप्रदायिक तनाव और छिटपुट घटनाएँ सामने आती रही हैं, जिन पर भारत में चिंता व्यक्त होती रही है। नई सरकार के लिए यह एक कसौटी होगी कि वह कानून-व्यवस्था को निष्पक्ष और कठोर बनाए रखे तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या भेदभाव पर त्वरित कार्रवाई करे।

बीएनपी की जीत को कट्टरपंथी राजनीति की अस्वीकृति के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जमात-ए-इस्लामी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। यह संकेत देता है कि मतदाता अतिवादी एजेंडे से दूरी चाहते हैं। यदि नई सरकार इस जनादेश को समझते हुए समावेशी शासन का मॉडल अपनाती है, तो हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बन सकता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक स्पष्टता से सुनिश्चित होती है। तारिक रहमान के सामने अवसर है कि वे अपनी सरकार को आधुनिक, आर्थिक सुधारों पर केंद्रित और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देने वाली सरकार के रूप में स्थापित करें।

भारत के दृष्टिकोण से देखें तो नई दिल्ली की नीति आमतौर पर व्यक्तियों के बजाय संस्थागत संबंधों पर आधारित रही है। चाहे ढाका में अवामी लीग की सरकार रही हो या अब बीएनपी की, भारत का प्रयास रहेगा कि सहयोग के मौजूदा ढांचे को बनाए रखा जाए। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दे दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े हैं। यदि नई सरकार इन क्षेत्रों में निरंतर सहयोग बनाए रखती है, तो द्विपक्षीय विश्वास बना रहेगा।

हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल अक्सर भावनात्मक रूप ले लेता है, लेकिन इसका समाधान संस्थागत मजबूती में निहित है। बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की बात करता है, और वहां की न्यायपालिका तथा नागरिक समाज सक्रिय रहे हैं। यदि सरकार इन संस्थाओं को स्वतंत्र और प्रभावी बनाए रखती है, तो किसी भी समुदाय के साथ अन्याय की संभावना कम होती है। भारत भी राजनयिक माध्यमों से अपनी चिंताओं को रचनात्मक ढंग से रख सकता है, जैसा कि अतीत में होता आया है।

आर्थिक आयाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत-बांग्लादेश व्यापार लगातार बढ़ा है, और ऊर्जा सहयोग, रेलवे संपर्क तथा जलमार्ग विकास जैसी परियोजनाएँ दोनों देशों को परस्पर निर्भरता की दिशा में ले जा रही हैं। नई सरकार यदि आर्थिक सुधारों और निवेश को प्राथमिकता देती है, तो उसे क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता होगी। यह स्थिरता अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक शांति से सीधे जुड़ी है। इसलिए व्यावहारिक राजनीति की मांग है कि सरकार किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक अस्थिरता को बढ़ावा न दे।

तारिक रहमान के लिए यह भी एक अवसर है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश की सकारात्मक छवि को पुनर्स्थापित करें। लंदन से लंबे निर्वासन के बाद उनकी वापसी और भारी जनसमर्थन ने उन्हें एक नई वैधता दी है। यदि वे इस वैधता का उपयोग समावेशी शासन और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंधों के लिए करते हैं, तो भारत-बांग्लादेश संबंधों में नई ऊर्जा आ सकती है। भारत भी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ढाका के साथ रचनात्मक संवाद को प्राथमिकता देगा।

बीएनपी की जीत को केवल सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि बांग्लादेशी लोकतंत्र की एक नई परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। हिंदू समुदाय की सुरक्षा इस परीक्षा की एक महत्वपूर्ण कसौटी होगी। यदि नई सरकार कानून के शासन को सर्वोपरि रखती है और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव पर सख्ती से नियंत्रण करती है, तो न केवल हिंदू सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंध भी अधिक परिपक्व और स्थिर बनेंगे। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि ढाका की नई सत्ता समावेश और सहयोग की राह चुनती है या राजनीतिक ध्रुवीकरण की। फिलहाल संकेत यही हैं कि जनादेश स्थिरता और व्यावहारिकता के पक्ष में है, और यही दोनों देशों के साझा हित में भी है।

संपादकीय

संसदीय विमर्श के नए मानक और राघव चड्ढा की तथ्यपरक राजनीति

भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद में जन सरोकारों की अभिव्यक्ति जब आंकड़ों की शुचिता और तार्किक प्रखरता के साथ होती हैए तो वह केवल राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज बन जाती है। हाल के वर्षों में राज्यसभा के पटल पर एक युवा सांसद के रूप में राघव चड्ढा ने जिस परिपक्वता और आर्थिक समझ का परिचय दिया हैए उसने संसदीय विमर्श के स्तर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। विशेष रूप से वर्ष 2026 के बजटीय सत्र के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य भारत की बदलती कर संरचना और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंतन की मांग करते हैं। एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पृष्ठभूमि होने के कारण चड्ढा का दृष्टिकोण केवल भावनात्मक नहीं बल्कि पूर्णतः गणितीय और वस्तुनिष्ठ होता है। उन्होंने इस तथ्य को मजबूती से रेखांकित किया है कि वर्तमान में देश का मध्यम वर्ग सरकार के लिए एक मूक स्वचालित टेलर मशीन ;एटीएमद्ध बनकर रह गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसारए भारतीय कर इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब व्यक्तिगत आयकर का संग्रह कॉर्पोरेट कर की तुलना में अधिक हो गया है। फ़रवरी 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो प्रत्यक्ष कर संग्रह 19ण्44 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया हैए जिसमें गैर.कॉर्पोरेट यानी व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान 10.03 लाख करोड़ रुपये रहाए जबकि बड़े कॉर्पोरेट घरानों का योगदान 8.90 लाख करोड़ रुपये पर सिमट गया। यह विडंबना ही है कि जो वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जो ईमानदारी से कर का भुगतान करता हैए उस पर कर का बोझ 5.91 प्रतिशत की दर से बढ़ा हैए जबकि बड़े उद्योगों को मिलने वाली रियायतें उनके कुल योगदान को कम कर रही हैं। यह असंतुलन केवल सांख्यिकीय त्रुटि नहीं हैए बल्कि एक गहरी नीतिगत खामी की ओर संकेत करता है। चड्ढा ने संसद में इस बात को प्रमाणों के साथ रखा कि मध्यम वर्ग न केवल प्रत्यक्ष कर के बोझ तले दबा हैए बल्कि महंगाई की दोहरी मार भी झेल रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत में महंगाई दर 6ण्8 प्रतिशत दर्ज की गईए जिसमें शिक्षा पर खर्च में 8 प्रतिशतए स्वास्थ्य सेवाओं में 9 प्रतिशत और आवास के किराए में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इन परिस्थितियों में वेतनभोगी वर्ग के पास बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए मानक कटौती की सीमा को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1ण्5 लाख रुपये करने का जो प्रस्ताव दियाए वह करोड़ों करदाताओं की अंतरात्मा की आवाज बनकर उभरा।

संसदीय वाद.विवाद में चड्ढा का योगदान केवल करों तक सीमित नहीं रहा हैए बल्कि उन्होंने लोक स्वास्थ्य के उस भयावह पहलू को भी छुआ है जिसे अक्सर विकास की चकाचौंध में अनदेखा कर दिया जाता है। फ़रवरी 2026 में उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट के संकट को एक राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा दी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शोधों का हवाला देते हुए बताया कि किस प्रकार भारतीय मसालों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में हानिकारक कीटनाशकों की उपस्थिति पाई गई हैए जिन्हें विकसित देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन पदार्थों में कैंसरकारी तत्वों की मौजूदगी राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अधिक स्वायत्तता और दंडात्मक शक्तियाँ देने की वकालत की ताकि गुमराह करने वाले विज्ञापनों और स्वास्थ्य के शत्रुओं पर लगाम कसी जा सके। इस मुद्दे की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके तर्कों के बाद सरकार को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश देने पड़े। स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी कमियों पर बोलते हुए उन्होंने अस्पतालों में बिस्तरों की कमीए चिकित्सकों पर कार्य का अत्यधिक दबाव और शल्य चिकित्सा के लिए मिलने वाली लंबी प्रतीक्षा तिथियों को मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताया। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की सफलता को एक राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रस्तुत कियाए जहाँ मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्थाओं ने प्राथमिक चिकित्सा को सुलभ बनाया है। उनके अनुसारए जब तक राष्ट्र के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों पर खर्च नहीं होगाए तब तक विकसित भारत का सपना केवल कागजों तक सीमित रहेगा।

वित्तीय संघवाद और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता पर भी चड्ढा के विचार अत्यंत मौलिक और प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की प्रकृति पर सवाल उठाया। वर्तमान व्यवस्था में केंद्र राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए जो सहायता देता हैए वह अक्सर कड़ी शर्तों और ऋण के रूप में होती है। चड्ढा ने मांग की कि राज्यों को ऋण के बजाय सीधे पूंजीगत अनुदान दिए जाने चाहिए। उन्होंने 1ण्5 लाख करोड़ रुपये के अनुदान का जो खाका प्रस्तुत कियाए उसका उद्देश्य राज्यों को सिंचाईए सड़क और शहरी बुनियादी ढांचे में स्वतंत्र रूप से निवेश करने हेतु सक्षम बनाना है। यह दृष्टिकोण सहकारी संघवाद की उस भावना को पुष्ट करता है जहाँ राज्य केवल केंद्र के अभिकर्ता न होकर विकास के बराबर के भागीदार होते हैं। इसके अतिरिक्तए उन्होंने लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए श्राइट टू रिकॉलश् अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का मुद्दा उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। उनका प्रस्ताव है कि यदि कोई विधायक या सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता हैए तो 18 महीने के प्रदर्शन काल के बाद मतदाताओं के पास उसे पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 50 प्रतिशत मतदान की अनिवार्यता का सुझाव दियाए जो राजनीति में अपराधीकरण और अकर्मण्यता को समाप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

आर्थिक सुधारों की दिशा में चड्ढा ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया है। उनका सुझाव है कि भूमि अभिलेखों को ब्लॉकचेन तकनीक पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। भारत में दीवानी मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति विवादों से संबंधित होता हैए जिससे न केवल न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है बल्कि आर्थिक निवेश भी प्रभावित होता है। ब्लॉकचेन आधारित पारदर्शी व्यवस्था से इन विवादों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। साथ हीए उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर की जटिलताओं को दूर कर इसे अधिक सरल और व्यापक बनाने के लिए इसके दूसरे संस्करण की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका तर्क है कि जब तक घरेलू निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होगीए तब तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा। चड्ढा के भाषणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समस्या गिनाने के साथ.साथ समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वे आंकड़ों को इस प्रकार बुनते हैं कि सरकार के लिए उन्हें अनदेखा करना संभव नहीं होता। उनके संसदीय सफ़र का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे किसी विशेष दल की विचारधारा के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रहित के मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। उनकी प्रखरता ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि विपक्षी दल तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंए तो वे सरकार को लोक.लुभावन घोषणाओं के बजाय ठोस नीतिगत बदलावों के लिए विवश कर सकते हैं। अंततः राघव चड्ढा की राजनीति आंकड़ों की शुचिताए मध्यम वर्ग के अधिकारों की रक्षा और एक पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण के इर्द.गिर्द घूमती हैए जो आने वाले समय में भारतीय संसदीय परंपरा के लिए एक आदर्श मार्गदर्शिका सिद्ध होगी।

महेन्द्र तिवारी

प्रेम का उत्सव या बाज़ार का प्रभाव? वेलेंटाइन डे परंपरा, परिवर्तन और आज का युवा मन

प्रतिवर्ष 14 फरवरी को विश्वभर में प्रेम दिवस के रूप में 'वेलेंटाइन डे' मनाया जाता है। भारत में भी पिछले कुछ दशकों से यह दिन विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय हुआ है। हालांकि समाज का एक वर्ग इसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मानते हुए इसका विरोध करता रहा है, फिर भी यह सच है कि प्रेम जैसी सार्वभौमिक भावना किसी सीमा या संस्कृति की मोहताज नहीं होती। यदि हम इस दिन को केवल पश्चिमी परंपरा के चश्मे से देखने के बजाय व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समझें, तो पाएंगे कि प्रेम और वसंत का संबंध हमारी अपनी परंपराओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

वेलेंटाइन नामक संत के बारे में मान्यता है कि उन्होंने प्रेम को सामाजिक बंधनों से ऊपर माना और प्रेमी युगलों का विवाह करवाने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनकी शहादत प्रेम की पवित्रता और समर्पण का प्रतीक बन गई। भारतीय संदर्भ में देखें तो प्रेम की यह भावना कोई नई नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण और राधा का संबंध केवल लौकिक प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना गया है। कृष्ण का प्रेम मर्यादा और माधुर्य दोनों का अद्भुत संगम है। संस्कृत साहित्य में भी वसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु कहा गया है। कालिदास, भास और शूद्रक जैसे साहित्यकारों ने अपने नाटकों और काव्यों में वसंत को मिलन और अनुराग का प्रतीक बताया है। 'मदनोत्सव' और 'वसंतोत्सव' जैसी परंपराएं इस बात की साक्षी हैं कि प्रेम और उल्लास का उत्सव मनाना भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग रहा है। वेलेंटाइन डे के आसपास ही भारत में वसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी से लेकर होली तक का समय प्रकृति के नवोन्मेष का काल होता है। सरसों के पीले फूल, कोयल की कूक और मंद समीर वातावरण में एक मधुर भाव जगाते हैं। सूफी संतों ने भी वसंत को प्रेम और भक्ति से जोड़ा। अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए बसंत और होली के गीतों की रचना की। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम का उत्सव मनाने की परंपरा केवल पश्चिम की देन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी हिस्सा रही है। जहां तक 'बेलन टाइम डे' से 'वेलेंटाइन डे' तक की हास्यपूर्ण कथा का प्रश्न है, वह एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है, जो सामाजिक संबंधों में सम्मान और समानता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसका ऐतिहासिक आधार चाहे जो भी हो, संदेश यह है कि दांपत्य संबंध प्रेम और आदर पर आधारित होने चाहिए, न कि उत्पीड़न पर। आधुनिक समाज में भी यह संदेश प्रासंगिक है। आज के समय में युवाओं का वेलेंटाइन डे के प्रति बढ़ता आकर्षण कई कारणों से है। एक ओर वैश्वीकरण और सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में विश्वास करती है। उनके लिए यह दिन अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह प्रकट करने का अवसर है। वे इसे केवल प्रेमी-प्रेमिका के संबंध तक सीमित नहीं रखते, बल्कि मित्रता, पारिवारिक स्नेह और आत्म-प्रेम तक भी विस्तारित कर रहे हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में 'फ्रेंडशिप डे' या 'रोज डे' जैसी गतिविधियां युवाओं को अभिव्यक्ति का मंच देती हैं।

किन्तु इसके साथ कुछ प्रश्न भी जुड़े हैं। क्या प्रेम को केवल एक दिन तक सीमित कर देना उचित है? क्या उपहार, महंगे फूल और रेस्टोरेंट में डिनर ही प्रेम की अभिव्यक्ति हैं? आज वेलेंटाइन डे पर बाजार का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कंपनियां विशेष ऑफर और विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करती हैं। इससे प्रेम का भाव कहीं-कहीं प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेता है। जिन युवाओं के पास आर्थिक साधन कम होते हैं, वे स्वयं को हीन महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार प्रेम का सहज और सरल भाव उपभोगवाद की चकाचौंध में दब जाता है।

समाज पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार अपरिपक्व आयु में आकर्षण को प्रेम समझ लिया जाता है, जिससे भावनात्मक आघात या पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर दिखावटी रिश्तों का दबाव भी युवाओं को भ्रमित करता है। कुछ मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित व्यवहार सामाजिक असहजता का कारण बनता है। अतः आवश्यक है कि युवा प्रेम और आकर्षण के अंतर को समझें और अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें।

इसके विपरीत, यदि वेलेंटाइन डे को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो यह आपसी सम्मान, संवाद और संवेदनशीलता को बढ़ाने का अवसर भी हो सकता है। प्रेम केवल रोमांटिक संबंध नहीं, बल्कि सहानुभूति, करुणा और सहयोग की भावना है। यदि इस दिन को हम माता-पिता, मित्रों, शिक्षकों या समाज के जरूरतमंद लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में मनाएं, तो इसका स्वरूप अधिक व्यापक और सार्थक हो सकता है। भारतीय संस्कृति 'वसुधैव कुटुंबकम्' का संदेश देती है, जिसमें समस्त विश्व को परिवार माना गया है। इस दृष्टि से प्रेम दिवस का अर्थ केवल युगल प्रेम तक सीमित नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों के सुदृढ़ीकरण से है। आज वेलेंटाइन डे आवश्यक है या नहीं, इसका उत्तर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। प्रेम तो हर दिन व्यक्त किया जा सकता है, फिर भी विशेष दिवस हमें ठहरकर अपने संबंधों को संवारने का अवसर देते हैं। यदि हम इसे अंधानुकरण या उग्र विरोध के बजाय संतुलित दृष्टिकोण से अपनाएं, तो यह सांस्कृतिक संघर्ष का कारण नहीं बनेगा। भारतीय समाज की विशेषता यह रही है कि उसने बाहरी प्रभावों को आत्मसात करते हुए उन्हें अपनी संवेदना के अनुरूप रूपांतरित किया है। ठीक उसी प्रकार वेलेंटाइन डे को भी हम भारतीय मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं। अंततः प्रेम एक सार्वभौमिक और शाश्वत भावना है। इसमें वासना नहीं, बल्कि समर्पण और सम्मान का भाव होना चाहिए। चाहे वह राधा-कृष्ण का आध्यात्मिक प्रेम हो, सूफी संतों की भक्ति हो या संत वेलेंटाइन की शहादत। सभी का मूल संदेश यही है कि प्रेम मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रेम को दिखावे या बाजारवाद से ऊपर उठाकर उसकी पवित्रता को बनाए रखें। यदि वेलेंटाइन डे हमें यही सीख देता है, तो यह केवल एक विदेशी पर्व नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का उत्सव बन सकता है।

कांतिलाल मांडोत

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत के मामले में अज्ञात चालक पर मामला दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली रोड पर बाल्हेमऊ गांव के निकट सड़क हादसे में हुई एक बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने बाइक के अज्ञात चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज किया है।कालिकाबख्श का पुरवा मजरे ऐहार गांव निवासी धर्मेंद्र ने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनके बाबा बद्री प्रसाद साहू (80) बृहस्पतिवार को साइकिल से घर लौट रहे थे। हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पति की मौत के बाद पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के शोभवापुर गांव के निकट आठ फरवरी को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। अब मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। सरेनी थाना क्षेत्र के रावतपुर कला गांव निवासिनी सुमन ने प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि आठ फरवरी को उनके पति तेज बहादुर अपने चचेरे भाई रामप्रसाद और सेमरपहा गांव निवासी रिश्तेदार धुन्नर के साथ बाइक से गांव लौट रहे थे। तभी शोभवापुर गांव के निकट सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद तेज बहादुर को मृत घोषित कर दिया। अन्य दो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही।

बलिया में कांग्रेस की 'मनरेगा बचाओ पदयात्रा', बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल

बलिया। मनरेगा योजना में कथित कटौती और अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को बलिया में 'मनरेगा बचाओ पदयात्रा' निकाली। पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने किया। पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश पांडे, ओमप्रकाश तिवारी, पुनीत पाठक, विजय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए जीवनरेखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा के बजट में कटौती की जा रही है और समय पर मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा को मजबूत करने और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मनरेगा के बजट में वृद्धि तथा पारदर्शिता की मांग की। अंत में पार्टी नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि मनरेगा के तहत सभी पात्र लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और लंबित भुगतान शीघ्र कराया जाए। पदयात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

लखनऊ में अग्निवीर जीडी बनने के लिए 794 युवाओं ने लगायी दौड़, हमीरपुर और उन्नाव के अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा

लखनऊ। सेना भर्ती कार्यालय लखनऊ की ओर से छावनी के एएमसी स्टेडियम में चल रही रैली के आठवें दिन शुक्रवार को हमीरपुर और उन्नाव जिले के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर जिले की हमीरपुर, राठ, सेरीला और मौदहा व उन्नाव जिले की सफीपुर, हसनगंज, उन्नाव, पुरवा, बीघापुर और बांगरमऊ तहसीलों के 1083 अभ्यर्थियों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) के लिए बुलावा पत्र भेजा गया था। रैली में 794 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। शनिवार को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए गोंडा जिले की गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज व बांदा जिले के अंतर्गत बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी और पैलानी तहसीलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संकुल शिक्षकों की त्रैमासिक कार्यशाला सम्पन्न

● 1100 संकुल शिक्षकों को मिला निपुण विद्यालय लक्ष्य पर केंद्रित प्रशिक्षण:- शरद कपूर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद सीतापुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) खैराबाद में संकुल शिक्षकों की एक दिवसीय त्रैमासिक कार्यशाला का आयोजन 9 फरवरी से 13 फरवरी तक किया गया। पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जनपद के सभी ब्लॉकों के कुल 1100 संकुल शिक्षकों को एक-एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में एसआरजी करुणेश मिश्र, आलोक श्रीवास्तव, मदनेश मिश्र एवं अनुराग तिवारी द्वारा सारगर्भित प्रशिक्षण दिया गया। करुणेश मिश्र ने शिक्षकों से कहा कि विद्यालयों में बच्चों का सुव्यवस्थित आकलन कर उन्हें स्तरानुसार विभाजित करते हुए उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, जिससे निर्धारित समय में शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। आलोक श्रीवास्तव ने गणित शिक्षण में 4-ब्लॉक मॉडल, दक्षता आधारित शिक्षण, प्रिंट रिच सामग्री एवं बच्चों द्वारा निर्मित टीएलएम के प्रयोग पर जोर दिया। वहीं मदनेश मिश्र और अनुराग तिवारी ने पठन एवं लेखन क्षमता विकास को प्रभावी बनाने के उपाय बताए। कार्यशाला में शिक्षक डायरी नियमित भरने, गणित-विज्ञान किट के प्रयोग, तथा जिला स्तर पर जारी 31 बिंदु व 21 बिंदु की एसओपी के अनुपालन पर भी बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि इन बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य कर विद्यालयों को निपुण एवं आदर्श बनाया जा सकता है।

तालगांव में मनाया गया वार्षिकोत्सव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

तालगांव सीतापुर विकासखंड परसेंडी क्षेत्र के लाला भैरव प्रसाद राज श्री कान्वेंट स्कूल तालगांव में वार्षिकोत्सव 2026 उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय विविधता में एकता था कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10बजे विद्यालय प्रधानाचार्य राजेश श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ हुई छात्रों ने मनमोहक स्वागत नृत्य पेश किए, प्रधानाचार्य ने विद्यालय की वर्ष रिपोर्ट पेश की जिसमें विद्यालय के शैक्षणिक एवं खेल प्रतियोगिताओं को रेखांकित किया गया छात्रों ने विभिन्न लोक नृत्य,नाटक एवं गायन प्रस्तुत किए जिसने दर्शकों का मन मोह लिया विद्यालय प्रधानाचार्य राजेश श्रीवास्तव ने मेधावी छात्रों को अनेकों पुरस्कारों से पुरस्कृत किया और छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामने दी। प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों पर जोर दिया साथ ही प्रबंधक ने बताया छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है जिससे छात्रों पर मानसिक तनाव न रहे इस मौके पर डॉक्टर मुजीबुर्रहमान प्रधान मिर्किलीपुर, अर्पित वर्मा सदस्य जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी, डॉक्टर सोनू शुक्ल जिला पंचायत प्रत्यासी, के पी सिंह पूर्व मंगल अध्यक्ष पचदेवरा, सहित क्षेत्र के अभिभावक एवं सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय मौजूद रहे।

लखनऊ में आधी रात घर में लगी आग, रिटायर्ड सैन्यकर्मी की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

लखनऊ। पीजीआई क्षेत्र की वृंदावन योजना सेक्टर-6 सी में गुरुवार देर रात शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर शुरू हुई और देखते ही देखते कमरे में रखा फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने लगा। दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार की नींद धमाके जैसी आवाज से खुली। नीचे पहुंचने पर कमरा धुएं से भरा मिला। मकान स्वामी सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी आर पी सिंह ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मुख्य बिजली सप्लाई बंद कर दी। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे और सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान सिंह की उंगलियां हल्की झुलस गईं। समय रहते प्रयास होने से बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड या पुलिस को नहीं दी गई है।

त्यौहार/पर्व आपसी सद्भाव, अमन चैन के साथ मनाया जाए: डीएम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में आगामी त्यौहार/पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों, धर्मगुरूओं, मौलवी/ मुअज्जिज/ व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों/संभ्रांत नागरिकों के साथ सेन्ट्रल पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में जिलाधिकारी ने आगामी दिनो में होने वाले महाशिवरात्रि, रमजान एवं होली के पर्व को जनपद में शांति एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मो के मतावलम्बियों को एक दूसरे का सम्मान करने के साथ ही भाई चारे की भावना के साथ पर्व मनाया जाना चाहिए। उपद्रव करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायें। उन्होंने जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों से त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से सतर्कता बरतने के निर्देश दिये और कहा कि शिवरात्रि, शिवमन्दिरों में जलाभिषेक, गंगा स्नान त्यौहार/पर्व में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत थानावार पीस कमेटी की बैठक मौलवी/मुतवल्ली से समस्याओं/विवाद की जानकारी प्राप्त कर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से शीघ्र उसका समाधान करा लें। समस्त कार्यक्रम परम्परागत ढंग से ही सम्पन्न कराये जाये एवं कोई नवीन परम्परा को उत्पन्न न होने दिया जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा स्नान घाट, शिवमन्दिरों पर जलाभिषेक/होलिका दहन, होली जुलूस हेतु जाने वाले आवागमन मार्गो का पूर्व निरीक्षण कर लिया जाये और मार्गो पर पड़ने वाली बाधाओं जैसे बिजली/टेलीफोन के तारों का लटकना, मार्गो पर गड्ढे होना, जलभराव होना आदि का पूर्व से निराकरण कर लिया जाये। फाल्ट ठीक करने के लिए कार्मिकों की रोस्टरवार तैनाती की जाय। जिससे विद्युत फाल्ट समय से ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। सर्वजनिक मार्गो पर सड़को को अवरूद्ध कर कोई भी आयोजन नहीं किये जाये। निराश्रित, पशुओं के विचरण को नियंत्रित किया जाये। वाहनों से स्टंटबाजी करने, अवैध प्रेशर हार्न, हूटर आदि पर सख्त कार्यवाही की जाये। लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आयोजन स्थलों की सड़क मार्गो की मरम्मत करा ली जाये।

पर्वो पर प्रयुक्त होने वाले स्थलों/मार्गो की अनिवार्यतः साफ-सफाई कराई जाए, पानी और बिजली की नियमित आपूर्ति की जाये। नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा सफाई का कार्य सम्पन्न कराया जाये। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार जबरन रंग लगाने आदि का कार्य न होने पाये। प्रत्येक कार्यक्रम स्थलों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटी खोया, पनीर, दूध, दही, मिठाई, इत्यादि खाद्य पदार्थो की सघन चेकिंग कराई जाये। मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री कदापि न होने पाये। अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर एम्बुलेंस के साथ चिकित्सकों की तैनाती की जाये। लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किया जाये। अलविदा जुमा/ईद पर नमाज अदा किये जाने वाले मस्जिद/ईदगाह की सूची तैयार की जाए, प्रत्येक स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया जाये। अलविदा जुम्मा की नमाज ईद की नमाज के समय कतिपय मस्जिद/ईदगाह पर काफी संख्या में नमाजियों के एकत्र होने से भीड़-भाड़ व आवागमन को सुचारू बनाये रखने हेतु प्रभारी क्षेत्राधिकारी यातायात आवश्यक रूट डायवर्जन एवं उन स्थानों पर पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी अवश्य लगाई जाये। पुलिस अधीक्षक ने जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों से कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्रों का पूरी तरह भ्रमण तथा निरीक्षण कर लें और कोई नई परंपरा की शुरुआत न की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा, नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार सहित समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, संबंधित विभागीय अधिकारी तथा शान्ति समिति के सदस्य एवं प्रमुख संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे।

दंगल में दिखा पहलवानों का दम, चौरी चौरा के गोविंद पहलवान ने लखनऊ के मानसिंह पहलवान को दिखाया आसमान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर, भनवापुर क्षेत्र के सोहना चौराहे पर आयोजित तीन दिवसीय विराट कुश्ती दंगल के दूसरे दिन शुक्रवार को देश-विदेश से आए पुरुष एवं महिला पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। रोमांचक मुकाबलों के बीच कई पहलवानों ने अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देकर जीत दर्ज की। सोहना बाजार में आयोजित क्रांतिकारी हिंदू-मुस्लिम एकता विराट कुश्ती दंगल में पुरुष वर्ग के मुकाबले काफी रोचक रहे। जम्मू-कश्मीर के भूरा पहलवान ने राजस्थान के राजू पहलवान को शानदार दांव-पेंच के साथ पराजित किया। वहीं नेपाल के लकी थापा ने हरियाणा के सोनू को मात दी। सहारनपुर के शाहिल ने कानपुर के मनीष को चित कर जीत हासिल की। चौरीचौरा के गोविन्द ने लखनऊ के मानसिंह को हराया। अयोध्या के बाबा गौरी शंकर ने पंजाब के विक्की पहलवान को रोमांचक मुकाबले में पराजित कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

महिला वर्ग के मुकाबले भी बेहद आकर्षक रहे। गोण्डा की शिवांगी पहलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इलाहाबाद की रोशनी तथा दिल्ली की लाडो को पटखनी देकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके शानदार खेल की दर्शकों ने जमकर सराहना की। दंगल के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दर्शक मौजूद रहे और पहलवानों का उत्साहवर्धन करते रहे। इस अवसर पर आयोजक मनीष सिंह क्रांतिकारी, नसीम राइनी, कान्हा सिंह, कालू सहित दंगल समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

सरोजनीनगर में ग्राम समाज की छह करोड़ की जमीन से हटवाया अवैध कब्जा, चार हजार वर्गफुट जमीन से हटवाया गया अतिक्रमण

सरोजनीनगर। तहसील क्षेत्र के ग्राम मिरानपुर पिनवट में शुक्रवार को ग्राम समाज की भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने करीब चार हजार वर्गफुट क्षेत्र को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब छह करोड़ रुपये बताई गई है। नायब तहसीलदार नगर निगम तेजस्वी प्रकाश ने बताया कि टीम ने जेसीबी की सहायता से अस्थाई निर्माण को हटवाया। अधिकारियों ने बताया कि जमीन पर अवैध निर्माण की कोशिश की जा रही थी, जिसे हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति के कारण विरोध बढ़ नहीं सका। राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह भूमि ग्राम समाज के नाम दर्ज है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

तालगांव में द फैशन हाउस शोरूम का भव्य हुआ शुभारंभ

तालगांव सीतापुर परसेंडी क्षेत्र के तालगांव में द फैशन हाउस रेडिमेट शोरूम का भव्य शुभारंभ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेश शुक्ल व नि.वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी सुनील वर्मा ने फीता काटकर किया आए हुए अतिथि ने शोरूम के शुभारंभ के मौके पर क्षेत्रीय लोगों को बताया कि यह शोरूम क्षेत्र वासियों के लिए नया अनुभव प्रदान करेगा साथ ही क्षेत्र की जनता को रेडिमेड खरीदने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा उचित छूट पर कपड़े मिलेंगे। यह शोरूम प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगा शोरूम प्रोपराइटर प्रशांत गुप्ता ने बताया शोरूम के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को कम दामों में रेडिमेट की बिक्री की जाएगी जिससे क्षेत्र वासियों में खुशी बनी रहे आए हुए मुख्य अतिथियों को व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुरेश गुप्ता व डॉक्टर अमित गुप्ता ने अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सतीश गुप्ता ,राजेश गुप्ता, कृष्णपाल सिंह पचदेवरा, मुन्ना सायल पूर्व प्रधान तालगांव, ओम प्रकाश शुक्ल प्रधान राही, श्रवण प्रधान कैमहरा वजीरपुर,सगीर मिस्त्री, सूरज गुप्ता, रमेश गुप्ता, शिवप्रकाश सिंह पचदेवरा, डॉक्टर रामपाल वर्मा सहित क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के स्टूडेंट चैप्टर का उद्घाटन किया गया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज दिनांक 13/02/2026 को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के तत्वावधान में श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, लखनऊ में स्टूडेंट चैप्टर का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) भावेश कुमार चौहान एवं आईईआई, उत्तर प्रदेश संस्था के अध्यक्ष इं. विजय प्रताप सिंह के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर इं. पंकज अग्रवाल (कार्यकारी निदेशक) की गरिमामयी उपस्थिति रही। आईईआई, उत्तर प्रदेश संस्था के अध्यक्ष इं. सिंह ने स्टूडेंट चैप्टर की स्थापना के उद्देश्य एवं इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह मंच विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व क्षमता एवं पेशेवर दक्षता के विकास हेतु महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्था की विभिन्न तकनीकी गतिविधियों–सेमिनार, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां एवं प्रतियोगिताएं–के बारे में जानकारी दी तथा छात्रों को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में आईईआई, उत्तर प्रदेश संस्था के वरिष्ठ सदस्य इं. ए. के. सिंह, मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, इं. जे. बी. सिंह इं. आशीष यादव उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन, इं. सी. के. मंगलम (अधीक्षण इंजीनियर, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन) एवं इं. एन. के. निषाद, मानद सचिव, की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रोफेसर (डॉ.) मनीष निगम (उप निदेशक एवं विभागाध्यक्ष), प्रोफेसर (डॉ.) पारुल गुप्ता (उप निदेशक), इं. पूजा अग्रवाल (अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक) सहायक प्राध्यापक इं. नेहा सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि स्टूडेंट चैप्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, उद्योग एवं अकादमिक जगत से जुड़ने तथा पेशेवर नेटवर्क विकसित करने का सशक्त अवसर प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभाग के रिसर्च स्कॉलर्स एवं छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे।

डीएम ने ग्राम चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं

● डीएम ने कम्पोजिट विद्यालय बहादुर नगर में एमडीएम शेड और स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सरकार के मंसानुसार वि0ख0 अमावां की ग्राम पंचायत बहादुर नगर के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। जिसमें उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से समस्याओं को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के सामने बिजली, सड़क, पेंशन आदि संबंधित मामले आए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं शीघ्र ही निस्तारित की जाएगी। जिलाधिकारी ने उपस्थित ग्रामवासियों से केन्द्र व राज्य सरकार की मिल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली। जिसके संबंध में ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें उक्त योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित कराया जाये कि सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलें और कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ परक योजनाओं से वंचित न रहे।

चौपाल में ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम, राशन वितरण प्रणाली, पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन योजना-ग्रामीण, राज्य/केन्द्रीय वित्त योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित आदि योजनाओं पर चर्चा की गयी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की हेल्प डेस्क लगाकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया एवं स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया ।चौपाल में व्यापक रूप से विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका योजना के विषय में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने कम्पोजिट विद्यालय बहादुर नगर में बच्चों के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) शेड और एक अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी दौरान जिलाधिकारी ने आयोजित ग्राम चौपाल में विज्ञान क्विज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कक्षा-8 की छात्रा सुश्री शिवांशी को साइकिल एवं कक्षा-08 के उमेश, विशाल, आदर्श, कक्षा-07 के सुरजीत को किट का वितरण कर सम्मानित किया तथा हौसिला स्वयं सहायता समूह , छाया स्वयं सहायता समूह , ज्ञान स्वयं सहायता समूह एवं राग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सामुदायिक निवेश निधि का 1.5 लाख धनराशि के डेमोचेक एवं ममता व शर्मिला को लखपति दीदी के रूप में आजीविका संवर्धन में उक्त कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र तथा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनान्तर्गत दयाराम, रामचरन, रामफेर एवं सविता को डीजल पम्प सेट का वितरण किया। जिलाधिकारी ने विद्यालय के समस्त बच्चों को स्टेशनरी किट भी वितरित किया।

इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 सतीश प्रसाद मिश्रा, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार, डी0सी0 एन0आर0एल0एम0 सविता सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, खंड विकास अधिकारी अमावां संदीप सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी अमांवा ऋचा सिंह, ग्राम प्रधान अमावां नीलम सिंह सहित अन्य अधिकारीगण व क्षेत्रीय निवासीगण उपस्थित रहे।

सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनायें त्योहार व पंचायत चुनाव:- उप जिलाधिकारी महमूदाबाद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। आगामी महाशिवरात्रि पर्व एवं रमजान त्योहार तथा पंचायत चुनावों के मद्देनजर सदरपुर थाना परिसर में शुक्रवार को उपजिलाधिकारी महमूदाबाद की अध्यक्षता में एक पीस कमेटी की बैठक आहूत की गई जिसमें क्षेत्र के कई दर्जन हिन्दू, मुस्लिम धर्मावलंबियों के अलावा तमाम संभ्रांत लोग शामिल हुए। इस बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। बैठक में भविष्य में आने वाले पर्वों, त्योहारों और पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए उपजिलाधिकारी के0के0 सिंह ने कहा कि जल्द ही महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और कुछ ही दिनों बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों का रमजान त्योहार भी शुरू हो रहा है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव का महापर्व भी प्रस्तावित हैं ऐसे में सभी जनसमुदाय से अपील है कि सभी पर्वों, त्योहारों और पंचायत चुनावों को बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनायें। कोई भी ऐसी हरकत न करें कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़े।

क्षेत्राधिकारी वेदप्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहार हमें आपसी सद्भाव बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। खुशी के साथ त्योहार मनायें लेकिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे माहौल खराब हो। उन्होंने कहा मोबाइल के व्हाट्सएप अथवा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की उत्तेजित टिप्पणियां न की जायें। इस बारे में कहीं भी कोई तनाव की स्थिति देखें तो पुलिस को अवगत करायें। क्षेत्र में शांति बनाए रखें। थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा ने कहा कि आने वाले आगामी त्यौहारों को आपसी हेलमेल भाईचारे व खुशी के साथ मनायें। कोई भी नई परम्परा न शुरू करें। त्योहार हम सबको खुशी का संदेश देते हैं। कभी किसी के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। मोबाइल सेटों पर कोई भी व्यक्ति धर्म अथवा राजनीति को लेकर गलत कमेंट्स न करे। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कई उपनिरीक्षकों के अतिरिक्त कई आरक्षी व क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान, बीडीसी, अनेक हिन्दू मुस्लिम धर्मावलम्बी एवं संभ्रांत लोग उपस्थिति थे।

श्रीभूमि टाउन में इस बार जनसंपर्क में समाजसेवी मुन्नी छेत्री की एक पहल देखी जा रही है, जो लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं

श्रीभूमि संवाददाता: असम में 26वीं विधान सभा चुनाव नजदीक आते ही पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संभावित प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए कोशिश चल रहा है. इसी बीच उत्तर करीमगंज के राजनीतिक परिदृश्य में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। समाजसेवी मुन्नी छेत्री, जो एक सामान्य परिवार से राजनीति में आई हैं, गुवाहाटी और दिल्ली की दौड़-धूप से दूर रहकर सीधे आम जनता के बीच जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। गांव-गांव में लोगों से संवाद स्थापित करने के बाद अब उन्होंने श्रीभूमि टाउन क्षेत्र में भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। हर जगह अब सिर्फ एक ही चर्चा है कि हम केवल मुन्नी छेत्री जैसे नेता चाहते हैं। अगर मुन्नी छेत्री बीजेपी से टिकट पाती हैं तो वे भारी वोटों से जीत सुनिश्चित कर सकती हैं। उत्तर करीमगंज क्षेत्र में भी यही माहौल देखने को मिल रहा है। मुन्नी छेत्री क्षेत्र के

विभिन्न गांवों, वार्डों और बाजारों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। समर्थकों के साथ बैठकें, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा और जनता से सीधा संवाद–इन सबके जरिए अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब केवल देखने की बारी है कि पार्टी की उच्च कमान क्या निर्णय लेती है। राजनीतिक आदर्श को सहित लोगों के और समाज के जन को महत्व देते हुए समाज के हित में काम कर रही है। मुन्नी छेत्री जैसी नेता को राजनीतिक मैदान में कितना मौका मिलेगा? इस समय यही सवाल उत्तर करीमगंज समुदाय में घूम रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी

संगठन स्थानीय जनता की भावनाओं और लोकप्रियता को कितना महत्व देता है। हालांकि इन सभी अटकलों के बीच मुन्नी छेत्री ने पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए अपना जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रखा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टिकट वितरण से पहले का यह समय बेहद अहम होता है। ऐसे में प्रत्येक दावेदार संगठन के शीर्ष नेतृत्व को अपनी लोकप्रियता और कार्यक्षमता दिखाने में जुटा है। अब सबकी नजरें पार्टी हाईकमान के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि उत्तर करीमगंज से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए।

संक्षिप्त खबरें

तुर्कमान गेट पथराव मामला: 12 आरोपियों की जमानत पर 16 फरवरी को आएगा कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। तीस हजारी एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान तुर्कमान गेट पर पथराव की घटना में गिरफ्तार 12 आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह घटना 6 जनवरी की रात को हुई थी, जब चांदनी महल पुलिस स्टेशन में स्रढ्ढक्र दर्ज की गई थी। एडिशनल सेशंस जज भूपिंदर सिंह ने आरोपियों के वकीलों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 16 फरवरी को अपना फैसला सुना सकता है।

जिन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की, उनमें मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, अदनान, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद उबैदुल्ला, आमिर हमजा, मोहम्मद आदिल, समीर हुसैन, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद अरीब शामिल थे। बचाव पक्ष ने दलील दी कि ज्यादातर आरोपी घटनास्थल के आसपास के रहने वाले हैं, इसलिए उनके मोबाइल फोन की लोकेशन फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास होना स्वाभाविक है। वकीलों ने दलील दी कि आरोपी अपने रिश्तेदारों की तलाश में वहां गए थे और पथराव में उनके शामिल होने का कोई CCTV सबूत नहीं है। एक आरोपी ने यह भी दलील दी कि उसने अपने मोबाइल फोन पर मिले भड़काऊ मैसेज नहीं बनाए थे, बल्कि उन्हें सिर्फ फॉरवर्ड किया था। बचाव पक्ष ने इंडियन पीनल कोड की धारा 307 (हत्या की कोशिश) लगाने को भी बहुत ज़्यादा बताया, और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी घायल को जानलेवा चोट लगने की बात सामने नहीं आई। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया। प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई थी, और आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों पर पथराव करके कानून-व्यवस्था पर हमला किया था। पुलिस ने सबूत के तौर पर WhatsApp मैसेज और वीडियो का हवाला दिया।

बांग्लादेशी नाबालिग दुष्कर्म का मामला, आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

» दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी।

» सात साल से जेल में बंद था आरोपी।

» पॉक्सो एक्ट के बावजूद मिली राहत।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी नाबालिग से रेप के आरोप में सात साल से जेल में बंद आरोपी को बेल पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस गिरीश कथपालिया की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आरोपी को सिर्फ इसलिए हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि मामला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन रेप की तारीखों या समय के बारे में कोई डिटेल नहीं दे पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैक्ट्स बताते हैं कि शिकायत करने वाली महिला ने आरोपी के साथ सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। यह कहते हुए, कोर्ट ने आरोपी को 10,000 के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की श्योरिटी पर बेल पर रिहा करने का आदेश दिया। पिटीशन के मुताबिक, नाबालिग बांग्लादेश की रहने वाली है और सिर्फ बंगाली बोलती है। उसने कहा कि आरोपी उसे नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली लाया और वहां उसने और दो अन्य लोगों ने उसके साथ कई बार रेप किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका नाम जाली बनाया और फिर उसे फरीदा बेगम नाम की एक महिला के लिए नौकरी दिलाने के लिए जयपुर ले गया। फरीदा बेगम और उनके पति के बीच झगड़ा हुआ और वह वहां से भागकर पुलिस स्टेशन चली गई।

भागते चीनी जहाज को जापान ने दबोचा, भारी एक्शन हो गया!

जापान की फिशरी एजेंसी ने इस बयान को जारी करते हुए बताया कि 12 फरवरी की दोपहर के आसपास नागासाकी प्रीफेक्चर के गोतो द्वीप समूह के पास मेशिमा द्वीप से लगभग 89.4 नॉटिकल मील यानी कि करीब 165 कि.मी. दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान की ईजेड में चीनी नाव क्यू ओंग डोंग यू 111998 को देखा गया।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब जापान भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में है। तभी तो साल 2022 के बाद अब जापान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। जापानी अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम जापान के नागासाकी के पास अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक चीनी मछली पकड़ने वाले नाव को जब्त कर लिया। उसके कप्तान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि नाव ने जापानी निरीक्षण टीम के आदेशों की अनदेखी कर भागने की कोशिश की। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और चीन के बीच पहले से ही एक बड़ा कूटनीतिक विवाद चल रहा है।

जापान की फिशरी एजेंसी ने इस बयान को जारी करते हुए बताया कि 12 फरवरी की दोपहर के आसपास नागासाकी प्रीफेक्चर के गोतो द्वीप समूह के पास मेशिमा द्वीप से लगभग 89.4 नॉटिकल मील यानी कि करीब 165 कि.मी. दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान की ईजेड में चीनी नाव क्यू ओंग डोंग यू 111998 को देखा गया। यह एक ट्रोलर प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव थी जिसमें जाले लगे हुए थे। फिश एजेंसी के पेट्रोल जहाज होकआ मारो ने नाव को रोकने और बोट पर निरीक्षण की

अनुमति देने का आदेश दिया। लेकिन कप्तान ने आदेश की अवहेलना की और नाव भगाने लगा। इसके बाद जापानी अधिकारियों ने नाव को जब्त कर लिया और उसके 47 वर्षीय चीनी कप्तान को भी गिरफ्तार किया गया।

नाव पर कुल 11 चालक दल के सदस्य थे जिनमें से कप्तान को हिरासत में लिया गया। बाकी सदस्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मीनारू केरा ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में इस घटना की पुष्टि की है और इस पर बयान भी दिया है। सुस सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब से ताइवान के मामले में जापान और चीन की टकराहट बढ़ी है। जापान ने वापस से परमाणु कार्यक्रम की तरफ कदम उठाने पर जोर दिया है। उसके बाद से ही यह तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साल 2022 के बाद पहली बार जापान ने चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया। हाल के वर्षों में जापान ने दक्षिण कोरिया और ताइवान की नाव को भी इसी तरह जब्त किया है।

महरौली-बदरपुर रोड पर मेट्रो निर्माण में हादसा, बीच सड़क पर क्रेन से गिरा पिलर

» एमबी रोड पर मेट्रो पिलर गिरने से बड़ा हादसा टला।

» घटना के बाद सड़क पर लगा लंबा यातायात जाम।

नई दिल्ली। एमबी रोड (महरौली-बदरपुर रोड) पर मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ा हादसा टल गया। मेट्रो का एक पिलर क्रेन की मदद से खड़ा किया जा रहा था, तभी वह अचानक गिर गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई व्यक्ति या वाहन नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि पिलर गिरने से सड़क पर काफी देर तक यातायात ठप रहा। चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन और अन्य मशीनों की मदद से पिलर को रास्ते से हटाया गया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। मेट्रो अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का फैसला किया है।

संभागीय परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित, चालकों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 11 फरवरी 2026 को संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय बस्ती में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद बस्ती के चालक, परिचालक एवं वाहन स्वामियों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुरेश कुमार मौर्य ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दोपहिया वाहन चालक सदैव हेलमेट का प्रयोग करें तथा चारपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की सख्त हिदायत दी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला वाजपेई ने अपील की कि सभी वाहन चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं आवश्यक प्रपत्रों के साथ ही वाहन चलाएं, ताकि दुर्घटनाओं और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। कार्यशाला में जिला अस्पताल के डॉक्टर तुलस्यान ने वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाना अत्यंत खतरनाक है।

नशा करने के बाद मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इस अवसर पर चालक, परिचालक, वाहन स्वामी एवं परिवहन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।

यूं जी सी अधिनियम 2026 केंद्र सरकार अभिलंब लागू करें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। भारतीय कुर्मी महासभा के द्वारा यूजीसी 2026 अधिनियम लागू करने के संबंध में भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ हरिश्चंद्र पटेल के निर्देशन पर एवं भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल के नेतृत्व में सैकड़ो अधिवक्ता पदाधिकारी के साथ जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय रामकिशोर पटेल ने कहा कि यूजीसी अधिनियम 2026 अभिलंब लागू करें। हमारी पहली मांग बहुजनों के ऊपरअत्याचार ना करें।

दूसरी मांग ओ बी सी का आरक्षण 27% एस सी, एस टी, को 22.5% पूरा आरक्षण दें।तीसरी मांग एनएफसी लिखकर फेल करने की प्रक्रिया तत्काल समाप्त करें। एवं 40% अंक साक्षात्कार समय अवश्य प्रदान करें। एवं चौथी मांग चौथी मांग लैटरल एंट्री द्वारा हो रही इस की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल बंद करें एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। अन्यथा तमाम संगठन जैसे भारतीय कुर्मी महासभा महासभा के साथ, बहुजन महासभा, मौर्य महासभा, पाल महासभा, यादव महासभा, पासी महासभा, बिंद महासभा, प्रजापति महासभा, आदि संगठन मिलकर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे द्य क्या पंडित देते समय हमारे समस्त पदाधिकारी गण अधिवक्ता परिषद के जिला महासचिव एडवोकेट संजय कुमार पटेल, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट धीरेंद्र सिंह पटेल, जिला संगठन सचिव एडवोकेट सुरेश कुमार पटेल, जिला संगठन सचिव इंजीनियर चंद्रभान सिंह पटेल, एडवोकेट शांति स्वरूप पटेल, एडवोकेट अमरेंद्र सिंह, एडवोकेट अजय कुमार, एडवोकेट छोटेलाल पाल, एडवोकेट भास्कर पासवान, एडवोकेट अशोक कुमार वर्मा, एडवोकेट वीरेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट शिव बालक

पटेल, एडवोकेट जितेंद्र सिंह, एडवोकेट धीरेंद्र सिंह, एडवोकेट कुमार सतीश सिंह,एडवोकेट रत्नाकर सिंह,एडवोकेट प्रदीप कुमार मंत्री, एडवोकेट धीरेंद्र कुमार भारतीया, एडवोकेट प्यारेलाल वर्मा, एडवोकेट सुनील कुमार सरोज, एडवोकेट रवि सोनकर उर्फ गोलू, एडवोकेट अखिलेश कुमार एडवोकेट ,कमलेश कुमार पटेल, एडवोकेट पिंटू सिंह, एडवोकेट के एन सिंह, एडवोकेट चंद्रमा सिंह पटेल, एडवोकेट कुलदीप सिंह आदि सैकड़ों लोग सम्मिलित रहे।

मुलायम सिंह का ऐलानः अधिवक्ताओं की हत्याओं का सिलसिला बंद हो, वरना आंदोलन होगा तेज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर देहात। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हो रही हत्याओं के खिलाफ तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और जीवन रक्षा मिलना अनिवार्य है लेकिन इसके अभाव में वे अपराधियों के निशाने पर आ रहे हैं।रामपुर में भरी कचहरी में अधिवक्ता फारूक अहमद खां की दिनदहाड़े गोली मार हत्या का हवाला देते हुए मुलायम सिंह ने जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पांच सूत्री मांगें स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए कहा गया हत्यारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाकर सख्त कार्रवाई मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये सहायता परिजनों में एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदेश की सभी अधिवक्ता हत्याओं की

उच्चस्तरीय जांच तथा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का शीघ्र लागूकरण किया जाए।

मुलायम सिंह बोले अधिवक्ता जनता को न्याय दिलाते हुए खूंखार अपराधियों से टकराते हैं और न्यायालय पर भी बेखौफ हत्याएं हो रही हैं यह असहनीय है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी न हुई तो आंदोलन तेज होगा।

न्यायालय में पूर्ण बहिष्कार का विरोधस्वरूप जनपद के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य विरत रखा। ज्ञापन सौंपने वालों में रमेश चंद्र सिंह गौर, दुर्गेश चंद्र, सर्वेंद्र सिंह, धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र बाबू, जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, प्रीति त्रिपाठी, संजय, आनंद मोहन कटियार, बलराम सिंह, महेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, अंकित मिश्रा, वेदव्यास निराला, राजेंद्र गुप्ता, सुबोध नारायण त्रिपाठी, एसके सिंह, रामशरण, सुलेखा, सरोज दीक्षित, संपत लाल, जय सिंह, रवि वर्मा, राम गणेश सविता, सुधीश पाल, कल्याण सिंह, अशोक श्रीवास्तव, दिलीप सिंह यादव आदि प्रमुख थे।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपी ने आजमगढ़ में लॉन्च किया अपना एडमीशन व स्कॉलरशिप पोर्टल सीयूसीईटी 2026

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आजमगढ़, 13 फरवरी। भारत आज न केवल दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। इसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस परिवर्तनकारी पहल का एक अहम उदाहरण उन्नाव में सामने आया है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक एआई-सपोर्टेड कैंपस स्थापित किया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एआई आधारित कैंपस स्थापित करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बन गई है। कानपुर-लखनऊ रोड पर उन्नाव के एससीआर क्षेत्र में स्थित यह कैंपस न केवल एआई-सपोर्टेड शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप इंडस्ट्री-रेडी वर्कफोर्स के रूप में भी तैयार कर रहा है। यह जानकारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के प्रो वाइस चांसलर डॉ. थिपेंद्र पी. सिंह ने आजमगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।

इस अवसर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश द्वारा अपने स्कॉलरशिप एवं एडमिशन पोर्टल 'सीयूसीईटी 2026' की आधिकारिक शुरुआत की गई। यूनिवर्सिटी ने इस पहल के तहत छात्र-छात्राओं को 50 करोड़ रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की, जिससे एआई, रिसर्च और इनोवेशन आधारित उच्च शिक्षा को अधिक व्यापक और सुलभ बनाया जा सके।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. थिपेंद्र पी. सिंह ने बताया कि सीयूसीईटी स्कॉलरशिप योजना ने अपने पहले ही शैक्षणिक सत्र में उल्लेखनीय प्रभाव दिखाया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 2,000 से अधिक विद्यार्थियों को करोड़ों रुपये की स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। इससे विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर और आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का दीर्घकालिक लक्ष्य राज्य को एआई आधारित शिक्षा, शोध और तकनीकी नवाचार का वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

यूनिवर्सिटी के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप फोकस को रेखांकित करते हुए डॉ थिपेंद्र पी सिंह, ने कहा कि 'कैम्पस टैंक' और 'सीयू एआई स्पेस' जैसी पहलें स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स को सीड फंडिंग, इनक्यूबेशन और पेटेंट फाइलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' द्वारा लॉन्च किए गए कैम्पस टैंक के माध्यम से अब तक 1,000 से अधिक स्टार्टअप्स को 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल द्वारा शुरू की गई नारी योजना टेक्नोलॉजी आधारित रिसर्च और इनोवेशन में महिलाओं के लिए नए अवसर सृजित कर रही है।

डॉ थिपेंद्र पी सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का एआई-एनहैंस्ड स्मार्ट कैंपस लगभग 2,500 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है, जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ एडवांस्ड रिसर्च को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। इस एकेडमिक इकोसिस्टम के तहत यूनिवर्सिटी ने 22 मल्टीडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो एग्रीकल्चर, डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम रिसर्च और साइबर सिक्योरिटी जैसे इमर्जिंग क्षेत्रों में रिसर्च को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि एक्सपीरिएंशल और इंडस्ट्री-बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। एप्पल विज़न प्रो लैब, एआई-एमएल रिसर्च सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रदान कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप एडवांस्ड क्रेडिट सिस्टम और स्किल-बेस्ड प्रोग्राम भी लागू किए गए हैं, ताकि छात्र करियर की शुरुआत से ही ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बन सकें।

इंटरनेशनल एमओयू और ग्लोबल इंडस्ट्री कोलैबोरेशनः डॉ सिंह ने बताया कि स्टूडेंट एक्सचेंज, जॉइंट रिसर्च और ग्लोबल इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए

यूनिवर्सिटी ने कई प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू साइन किए हैं। साथ ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम समेत 23 ग्लोबल कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन के जरिए एकेडमिक प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिससे स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी में स्पष्ट सुधार देखने को मिल रहा है। 2026-27 में 68 एआई-एनहैंस्ड एकेडमिक प्रोग्रामः उन्होंने जानकारी दी कि एकेडमिकसेशन 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी ने कुल 68 एआई-एनहैंस्ड और इंडस्ट्री-अलाइनड प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिनमें 40 अंडरग्रेजुएट, 16 पोस्टग्रेजुएट और 12 लेटरल एंट्री प्रोग्राम शामिल हैं। इनका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों को फ्यूचर-रेडी स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करना है।

पहले ही वर्ष में नेशनल लेवल पर मजबूत पहचानः यूनिवर्सिटी की तेज़ प्रगति का जिक्र करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि पहला वर्ष उपलब्धियों और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान का रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने देश की पहली प्राइवेट एआई-बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट एआई बूटकैंप, 60 से अधिक फ्री हाई-डिमांड एडवांस्ड क्रेडिट प्रोग्राम्स और 100 से ज्यादा कंपनियों वाला कॉरपोरेट एडवाइजरी बोर्ड यूनिवर्सिटी के इनोवेशन और प्लेसमेंट इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। करोड़ों रुपये की स्कॉलरशिप, जिनमें सी. वी. रमन स्कॉलरशिप भी शामिल है, मेधावी छात्रों को प्रेरित कर रही हैं, जबकि नए पीएचडी प्रोग्राम राज्य में रिसर्च कल्चर को नई दिशा दे रहे हैं।

एआई कन्वर्जेंस समिट और नेशनल इनिशिएटिव्सः डॉ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हाल ही में आयोजित एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 सेंट्रल गवर्नमेंट के अपकमिंग इंडिया एआई इम्पैक्ट ग्लोबल समिट 2026 (16-20 फरवरी, नई दिल्ली) का ऑफिशियल प्री-इवेंट रहा। इसमें पांच देशों के एआई व टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। 'क्वांटम फॉर भारत' मिशन और एआई हेल्थकेयर हैकाथॉनः समिट के दौरान यूनिवर्सिटी ने 'क्वांटम फॉर भारत' मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत को एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाना है। इसके साथ ही भारत का पहला एआई हेल्थकेयर हैकाथॉन भी आयोजित किया गया, जिसमें देशभर से 1,500 टीमें और 5,000 से अधिक युवा प्रतिभागी 100 से ज्यादा हेल्थकेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर एआई-आधारित समाधान विकसित कर रहे हैं। सीयूसीईटी 2026 पोर्टल लॉन्च, एडमिशन प्रक्रिया शुरूः इस अवसर पर डॉ थिपेंद्र पी सिंह ने सीयूसीईटी 2026 पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी https://cucet.cuchd.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 18002701411 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीयूसीईटी का उद्देश्य फाइनेंशियल बैरियर्स कम करना, एकेडमिक आकांक्षाओं को सपोर्ट करना और प्रदेश के युवाओं के लिए एआई-बेस्ड शिक्षा व रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

लाठी डंडा व सरिया से पीट कर युवक की हत्या, मामला दर्ज, सात आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नैनी, प्रयागराज। नैनी कोतवाली क्षेत्र के मड़ौका गांव में गुरुवार की देर रात शादी समारोह के दौरान लघुशंका करने को लेकर हुए विवाद के दौरान कुछ लोगों ने एक युवक की लाठी- डंडा व सरिया से पीट-पीटकर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना में मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनी कोतवाली क्षेत्र के मड़ौका गांव स्थित एक गेस्ट हाउस में बृहस्पतिवार की रात बारात आई थी। बताते हैं, कि शादी समारोह के दौरान गेस्ट हाउस के समीप लघु शंका करने को लेकर राजेश कुमार निषाद उर्फ नेता (42) वर्षीय पुत्र स्वर्गीय राम सुमेर निषाद की कुछ लोगों से कहा- सुनी हो गई। बात अधिक बढ़ने पर उन लोगों ने लाठी- डंडा व सरिया से पीट पीट कर राजेश कुमार निषाद की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। शोर गुल सुनकर परिवारीजन एवं काफी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। आनन- फाइन में इलाज के लिए उसे अस्पताल ले गए। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके मरने की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया। घटना में मृतक के भाई शेखर निषाद की तहरीर पर पुलिस ने मड़ौका निवासी सुनील कुमार कनौजिया, फूलचंद, अंकित कनौजिया, चंटन कनौजिया, बबलू, जितेंद्र, रतन, नीरज, मिथुन, राहुल, राजेश, बंटी समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना से दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी है।

देह व्यापारः स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, दिल्ली में 9 महिलाएं रेस्क्यू

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। लाजपत नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने साउथ-ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। टीम ने मौके से दो मैनेजरों को गिरफ्तार किया है और नौ महिलाओं को बचाया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अर्निश डी. सेनापति उर्फ राहुल और विपिन वशिष्ठ उर्फ रवि के रूप में हुई है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हेमंत तिवारी के मुताबिक, गुरुवार को लाजपत नगर-1 की एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर वेगास स्पा और फर्स्ट फ्लोर पर वेदिका वेलनेस स्पा में प्रॉस्टिट्यूशन चलने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छापा मारा और ग्राउंड फ्लोर पर मैनेजर के साथ पांच महिलाएं मिलीं। रिसेप्शन काउंटर पर एक दराज से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुईं। बाद में फर्स्ट फ्लोर पर एक अन्य मैनेजर के साथ चार महिलाएं मिलीं। पुलिस ने दोनों मैनेजरों को गिरफ्तार कर नौ महिलाओं को प्रॉस्टिट्यूशन से बचाया। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि वे स्पा सेंटर की आड़ में प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे थे और पैसे के बदले कस्टमर अरेंज करते थे। उन्होंने आगे बताया कि वे कस्टमर्स से पेमेंट लेते थे, कमीशन रखते थे और बाकी रकम महिलाओं में बांट देते थे। जांच में पता चला कि दोनों में से किसी का भी पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।